

एफएमसीजी उद्योग (FMCG)

द हिन्दू, (29 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में चालू वर्ष में एफएमसीजी उद्योग (Fast Moving Consumer Goods) में दो अंकों वाला विकास होने की सम्भावना जताई जा रही है।
 - हांलाकि, यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम है। क्योंकि गत वर्ष अच्छी अर्थव्यवस्था और घटी हुई मुद्रास्फीति के कारण इस क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ था।
 - गत वर्ष की वृद्धि के पीछे जीडीपी की वृद्धि तो थी ही, साथ ही जीएसटी प्रणाली के तहत निर्मातागण ने मार्जिन एक्स्प्रेसन का लाभ हस्तांतरित किया था।



A word cloud centered around the term "FAST-MOVING CONSUMER GOODS". The words are arranged in a circular, radiating pattern. Key terms include "FAST-MOVING", "CONSUMER", "GOODS", "GROCERY", "CHARACTERISTICS", "SUBSTANTIAL", "PERISHABLE", "DURABLE", "RATES", "DRINKS", "SELL", "TURNOVER", "ITEMS", "DETERIORATES", "OPERATE", "MAJOR", "HIGHLY", "FOODS", "PROFIT", "BIGGEST", "MAINLY", "RAPIDLY", "LOW", "PRODUCT", "QUANTITIES", "CUMULATIVE", "HIGH", "HARDO", "APPLIANCES", "KITCHEN", "CLEANING", "MONTHS", "SHORT", "CONTRASTS", "DAIRY", "TOILETTS", "MEAT", and "AT".

एफएमसीजी क्षेत्र

- एफएमसीजी भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा और सबसे बड़ा क्षेत्र है।
 - भारत में घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल से सम्बंधित उत्पादों का विक्रय समग्र FMCG विक्रय का 50% होता है।
 - ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, साथ ही उन्हें उत्पाद सरलता से उपलब्ध हो रहे हैं। इसका यह भी कारण है कि लोगों की जीवनशैली बदल रही है।
 - सरकार ने खाद्य संस्करण एवं एकल ब्रांड खुदरा बाजार में 100% और कई ब्रांडों वाले खुदरा बाजार में 51% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी है।

संदर्भ

- हाल ही में आर्वत सारणी (periodic table) के संयोजन की 150वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए UNESCO ने अंतर्राष्ट्रीय आर्वत सारणी दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है।

संबंधित मुख्य बिंदु

- इस सारणी को सबसे पहले 1869 में रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने प्रकाशित किया था।
 - इस सारणी में रसायनिक तत्त्वों को उनके अणु के अंदर प्रोटानों की संख्या और अन्य गुणों के अनुसार सजाया गया होता है।

अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी दिवस

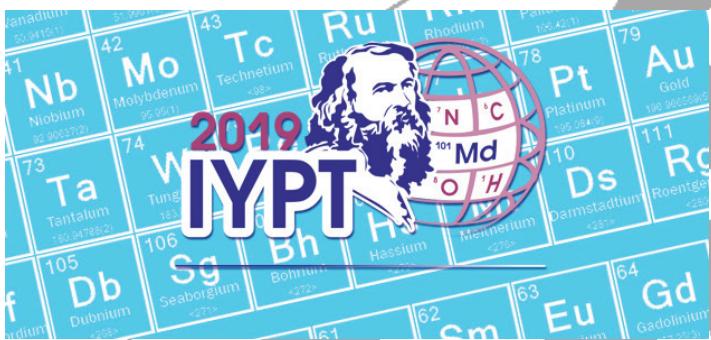
द हिन्दू, (29 Jan.)

द हिन्दू, (29 Jan.)

संदर्भ

- इस सारणी में सात कतारे होती हैं जिन्हें पीरियड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें 18 स्तम्भ भी होते हैं जो ग्रुप कहलाते हैं।

- सारणी में वर्णित एक ग्रुप के सभी तत्वों के गुण एक जैसे होते हैं। साथ ही एक पीरियड में दिखाए गये तत्वों के अणुओं के अंदर परिक्रमा करने वाले परमाणुओं की संख्या भी एक होती है।
- सारणी में वर्णित अधिकांश तत्व धातु तत्व होते हैं जिनकी छ: श्रेणियाँ होती हैं - क्षार धातुएँ, क्षारीय मृदा, बुनियादी धातुएँ, रूपांतरित होने वाली धातुएँ, लैंथेनाइड और एक्टीनाइड।
- ये सभी तत्व सारणी में बायीं ओर दिखाई जाती हैं, जबकि अधात्विक तत्वों को दाईं ओर एक टेढ़ी-मेढ़ी पंक्ति में सजाया जाता है।
- कई बार ऐसा होता है कि लैंथेनाइड और एक्टीनाइड एक अलग हिस्से में दिखाया जाता है।
- आवर्त सारणी उपयोगी होता है क्योंकि इससे लोग तत्वों के विभिन्न गुणधर्मों के बीच के सम्बन्ध को समझ सकते हैं।



कौन करता है आवर्त सारणी का संधारण?

- आवर्त सारणी के संधारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र संघ (International Union of Pure Applied Chemistry – IUPAC) उत्तरदायी होता है।
- यह एक ऐसा संघ है जिसमें अलग-अलग देशों के रसायनशास्त्री प्रतिनिधि होते हैं।
- इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड के ज्यूरिच शहर में है।
- इसकी स्थापना 1919 में हुई थी।



1001 आविष्कार

- यूनेस्को ने एक शैक्षणिक पहल करते हुए 1001 आविष्कार (1001 inventions) ऑल्केमी से रसायनशास्त्र तक की यात्रा का भी अनावरण किया है।
- इस पहल के अंतर्गत युवाओं को शैक्षणिक सामग्री और वैज्ञानिक प्रयोग की सुविधा दी जायेगी जिससे वे रसायनशास्त्र की अपनी समझ को बढ़ा सकें और उसके अनेक उपयोगों के बारे में जानें।
- 2019 में यह पहल पूरे विश्व के स्कूलों में लागू की जायेगी।



- इसमें यह देखा जाता है कि सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करने पर पकड़े जाते हैं अथवा वे बच निकलते हैं।
- यह सूचकांक एक मिश्रित सूचकांक है जिसमें देशों को रैंक देने के लिए 12 प्रकार के सर्वेक्षण किये जाते हैं।
- इस सूचकांक को विश्व में बहुत सम्मान दिया जाता है और विश्लेषक और निवेशक भ्रष्टाचार के मामले में इसे विश्वसनीय मानते हुए इसका उपयोग करते हैं।
- सूचकांक में 0 से लेकर 100 तक का एक मापदंड होता है जिसमें जीरो का अर्थ हुआ “बहुत अधिक भ्रष्ट” और 100 का अर्थ हुआ “सबसे साफ-सुथरा।

सूचकांक के निष्कर्ष

- सूचकांक के अनुसार डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है। उसको 100 में 88 अंक मिले हैं। उसके बाद क्रमशः न्यूजीलैंड और फिनलैंड का स्थान आता है।
- सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया को दिखाया गया है जिसे 10 अंकों के साथ सूचकांक के अंत में रखा गया है। इसके ऊपर दक्षिणी सूडान और सीरिया हैं।
- सूचकांक में जिन देशों का अध्ययन किया गया है उनमें 2/3 को 50 अंक से कम मिले हैं।
- ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका शीर्षस्थ 20 देशों में नहीं है क्योंकि उसको इसमें 22वाँ स्थान दिया गया है।
- ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था ने ब्राजील और अमेरिका को उन देशों की सूची में रखा था जिनके निरीक्षण की आवश्यकता है।





- यूरोप, जापान और रूस में सबसे अधिक बिजली की ट्रेनें हैं। दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देश आज भी डीजल पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- लगभग सभी जगह माल गाड़ियों की तुलना में सवारी गाड़ियाँ बिजली पर अधिक चलती हैं।
- बुलेट, मेट्रो आदि ट्रेनों को छोड़कर विश्व में अधिकांश रेलें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, भारत और जापान में संचालित होती हैं।
- वस्तुतः इन क्षेत्रों में विश्व-भर 90% यात्री यात्रा करते हैं। इनमें भी भारत (39%) और चीन (27%) सबसे आगे हैं।
- कई देशों में अब तीव्र गति की ट्रेनों और मेट्रो ट्रेनों में अच्छा-खासा निवेश हो रहा है। इस मामले में सबसे तेज विकास चीन में हुआ है।

भारत का प्रदर्शन

- इस बार भारत को 78वाँ स्थान मिला है जबकि पिछले वर्ष इसका स्थान 81वाँ था।
- जहाँ तक CPI अंकों की बात है तो भारत गत वर्ष की तुलना में एक अंक बढ़कर इस वर्ष 41 पर पहुँच गया है।

“रेल का भविष्य” नामक प्रतिवेदन

टाइम्स ऑफ इंडिया, (29 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने “रेल का भविष्य” नामक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है।
- इसमें यह पड़ताल की गई है कि वैश्विक परिवहन व्यवस्था में रेल की भूमिका को कैसे बढ़ावा दिया जाए कि जिससे ऊर्जा की खपत घटे और परिवहन के कारण पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव रोके जा सकें।



प्रतिवेदन के मुख्य बिंदु

- वस्तु और यात्रियों के लिए रेल सबसे अधिक ऊर्जा बचाने वाला परिवहन का साधन है। विश्व-भर में 8% यात्री और 7% माल रेल से ही आते-जाते हैं। लेकिन इनमें होने वाली ऊर्जा की खपत 2% मात्र होती है।
- आज के दिन में यात्रिक रेल परिचालन का भाग बिजली से चलता है जो वर्ष 2000 की तुलना में 60% अधिक है।



International
Energy Agency

भारत की स्थिति

- देश के विकास और लोगों तथा मालों के आवागमन में भारतीय रेल प्रणाली ने एक आधारभूत भूमिका निभाई है और देश के विभिन्न बाजारों और समुदायों को एकात्म किया है।
- 2000 की तुलना में भारत में रेल यात्रियों की संख्या में 200% और माल-हूलाई में 150% की वृद्धि हुई है। अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश बनी हुई है।
- भारत में पारम्परिक रेल पथों की कुल लम्बाई 68,000 किमी. के लगभग है। मेट्रो की गाड़ियाँ 10 शहरों में चल रही हैं और अगले कुछ वर्षों में 600 किमी. नई मेट्रो लाइनें बिछाने की योजना है। आज की तिथि में भारत के पास तीव्र गति की कोई रेल नहीं है। वर्तमान में अहमदाबाद और मुंबई के बीच एक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, जो 2023 में पूरी हो जाएगी।
- तीव्र गति की सात अन्य रेल लाइनों के निर्माण पर भी विचार चल रहा है। ये लाइनें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ेंगी और इनसे बीच-बीच के शहरों को भी लाभ होगा।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है?

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 1974 इसलिए की गयी थी कि उस वर्ष खनिज तेल की आपूर्ति में जो बाधाँ आई थीं उनका निराकरण किया जा सके। तब से इस निकाय की गतिविधियों में विविधता और विस्तार हुआ है।



प्रमुख कार्य

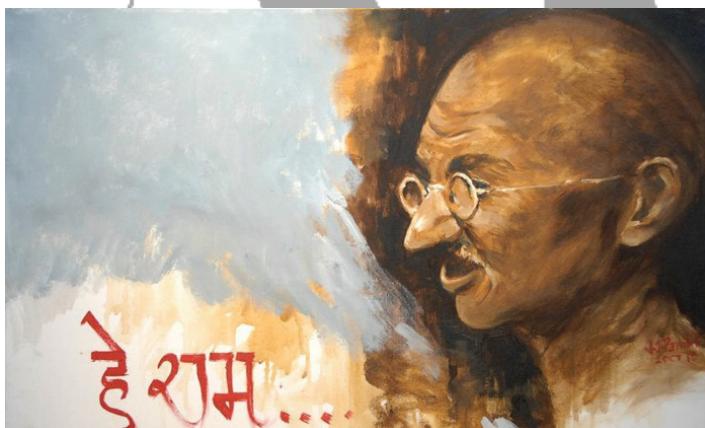
- यह ऊर्जा से सम्बंधित सभी विषयों की पड़ताल करता है, जैसे
 - तेल, गैस और कोयला आपूर्ति एवं माँग, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक, बिजली बाजार, ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा की उपलब्धता, माँग का प्रबंधन आदि।
- यह उन नीतियों का पक्षधर है जिनसे इसके सदस्य देशों और अन्य देशों में ऊर्जा की विश्वसनीयता, सुलभता एवं सततता में वृद्धि हो सकती है।
- यह प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि के लिए कार्यशालाओं, भाषणों एवं संसाधनों के कई कार्यक्रम चलाता ही है, इसके अतिरिक्त इसने कुछ प्रतिवेदन आदि भी प्रकाशित किये हैं।

नमक सत्याग्रह स्मारक

टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, (30 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में महात्मा गाँधी की 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुजरात के नवसारी जिल के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का लोकार्पण किया गया।
- इस स्मारक में महात्मा गाँधी के आदर्शों, यथा - स्वदेशी आग्रह, स्वच्छता आग्रह और सत्याग्रह का वर्णन एवं चित्रण हुआ है।



महत्त्व

- इस स्मारक का उद्देश्य राष्ट्र के लोगों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किये गये बलिदानों का स्मरण दिलाना है।
- साथ ही यह गाँधीजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले सत्याग्रहियों के प्रति श्रद्धांजलि भी है। यह स्मारक पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

नमक सत्याग्रह के बारे में

- मार्च 12, 1930 को महात्मा गाँधी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक नमक यात्रा आरम्भ की थी।
- यात्रा के अंत में वे दांडी नामक तटीय गाँव में पहुँचे थे और वहाँ ब्रिटिशों द्वारा नमक पर लगाये गये अत्यंत बढ़े हुए कर का विरोध किया था।

- यह नमक यात्रा 12 मार्च, 1930 से लेकर 6 अप्रैल, 1930 तक चली थी।
- 24 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा हिंसारहित रही और इसका यह ऐतिहासिक महत्त्व है कि इसके उपरान्त देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात हो गया।
- दांडी के समुद्र तट पर पहुँच कर महात्मा गाँधी ने अवैध रूप से नमक बनाकर कानून अवहेलना की थी।
- इनके देखा-देखी पूरे भारत में लाखों लोगों ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन किया जिसमें नमक बनाकर अथवा अवैध नमक खरीद कर नमक कानूनों को तोड़ा गया।



ऐतिहासिक भूमिका

- उस समय ब्रिटिशों ने भारतीयों को नमक बनाने और बेचने से मना कर दिया था। साथ ही भारतीयों को नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ को ब्रिटिशों से खरीदने के लिए विवश कर दिया था।
- इस प्रकार जहाँ ब्रिटिशों को नमक बनाने और बेचने का एकाधिकार प्राप्त हो गया था, वहाँ वे भारी नमक कर भी लगा रहे थे।
- नमक यात्रा ब्रिटिशों के इस अत्याचार के विरुद्ध एक जन-आन्दोलन में बदल गया।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

द. हिन्दू, (30 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में बजट सत्र के आरम्भ में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा संसद के एक संयुक्त अधिवेशन में संभाषण करने की संवैधानिक परम्परा रही है।
- इस परिपाठी का अनुपालन करते हुए इस वर्ष भी 1 फरवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान की धारा 87(1) के अनुसार, आम चुनाव के पश्चात् होने वाले संसद के पहले सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष होने वाले पहले सत्र के आरम्भ में राष्ट्रपति संसद की एक संयुक्त बैठक में अभिभाषण करेंगे।
- संविधान में इस प्रकार के अभिभाषण का प्रावधान प्रत्येक सत्र के लिए किया गया था।



- संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा इसे बदल दिया गया और ऐसे अभिभाषण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मात्र नई लोकसभा के पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरम्भ में हुआ करते हैं।



अभिभाषण में क्या होता है?

- राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुख्य रूप से आगामी वर्ष के संदर्भ में सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और योजनाओं की ओर ध्यान खींचा जाता है।
- यह अभिभाषण केन्द्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है।
- इसमें सरकार की कार्यसूची और काम करने की दिशा से सम्बंधित मोटे तौर पर जानकारी दी जाती है।

विश्व के सबसे लंबे 'गंगा एक्सप्रेस-वे' के निर्माण हेतु मंजूरी

फाइनेंसियल एक्सप्रेस, लाइव मिंट, (30 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 29 जनवरी, 2019 को प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक आयोजित की गई।



- इस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत 600 किलोमीटर लंबे 'गंगा एक्सप्रेस-वे' बनाने के फैसले पर मुहर लगाई गई है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा।

- प्रयागराज को पश्चिमी यूपी से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस-वे बनाने का फैसला लिया गया है। इसको बनाने में यूपी सरकार तकरीबन 36 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

गंगा एक्सप्रेस-वे के बारे में

- मेरठ से अमरोहा, बुलंदशहर, बदायू, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेस-वे प्रयागराज तक आएगा।
- 600 किमी लंबा यह चार लेन का एक्सप्रेस-वे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा।
- इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 6556 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी और करीब 36 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- इसके रास्ते में 6 रेलवे ओवरब्रिज और 18 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। यह लिंक रोड 91 किलोमीटर लंबा होगा। इसे बनाने में सरकार 5555 करोड़ रुपये खर्च करेगी।



विश्व का सबसे लंबा हाई-वे

- पैन अमेरिकन हाईवे: पैन-अमेरिकन हाईवे को दुनिया के सबसे लंबे वाहन चलाने योग्य सड़क के रूप में भी जाना जाता है।
- यह सड़क उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका की 30,000 मील की यात्रा तय करती है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है।
- यह दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों में पहले नंबर पर आता है।

6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी

टाइम्स नाउ, द ट्रिब्यून, (30 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से छह पनडुब्बियों के स्वदेश में निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।



फाइंनेंसियल एक्सप्रेस, (31 Jan.)

संदर्भ

- रक्षा मंत्रालय की यह परियोजना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी जो विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ मिलकर भारत में चुनिंदा सैन्य प्लेटफॉर्म बनाने के लिए निजी फर्म को जिम्मेदारी देने की व्यवस्था करता है।
- रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत लागू होने वाली यह दूसरी परियोजना होगी।
- नए मॉडल के तहत लागू होने के लिए सरकार की मंजूरी वाली पहली परियोजना 21 हजार करोड़ रुपये की लागत से नौसेना के लिए हेलिकॉप्टर की खरीद की थी।



मुख्य बिंदु

- इस परियोजना को प्रोजेक्ट 75 नाम दिया गया है। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) होगा, जिससे यह पनडुब्बियों 14 दिन तक जलमग्न रह सकती हैं।
- इस परियोजना को रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत मंजूरी दी गयी है। इस परियोजना को पूरा होने में एक दशक का समय लग सकता है।
- इस परियोजना के लिए भारतीय रक्षा निर्माता कंपनी विदेशी कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर कार्य करेगी।
- बैठक में रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 में महत्वपूर्ण बदलावों को भी मंजूरी दी गयी। बैठक में सेना के लिए लगभग 5000 मिलन टैक रोधी मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
- इससे पहले सरकार ने अगस्त, 2018 में इसी माडल के तहत नौसेना के लिए देश में ही 111 बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर बनाने की मंजूरी दी थी।



मुख्य बिंदु

- इस पेमेंट चैनल को जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने तैयार किया है। INSTEX का पूरा नाम 'इस्ट्रॉमेंट इन सोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज' है।
- ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद इस चैनल के जरिए कारोबारी भुगतान किया जा सकेगा।
- इसका बेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। जर्मनी के बैंकिंग एक्सपर्ट इसका प्रबंधन करेंगे। यूनाइटेड किंगडम सुपरवाइजरी बोर्ड की अगुवाई करेगा।
- यूरोपीय देश शुरू में इस चैनल के माध्यम से ईरान को भोजन, दवाएं और मेडिकल उपकरण बेचेंगे, लेकिन भविष्य में अन्य सेवाओं या उत्पादों को इसमें शामिल किया जा सकता है।
- बेल्जियम का कहना है कि ईरान को लेकर अमेरिका जो चिंताएं जताता है, यूरोप उनसे पूरी तरह सहमत नहीं है।
- यह कंपनियों पर निर्भर है कि वे ईरान में काम करना चाहती हैं या नहीं। लेकिन उन्हें भी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण सामने आए जोखिमों का ख्याल करना पड़ रहा है।
- यूरोप की इन कोशिशों को ईरान के साथ 2015 में हुई परमाणु संधि को बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।



रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी)

- रक्षा अधिग्रहण परिषद् का गठन सैन्य सामान शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए वर्ष 2001 में सरकार द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद् सैन्य सामान के अधिग्रहण के लिए दिशा-निर्देश भी जारी करता है।



पृष्ठभूमि

- अक्टूबर, 2015 में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान के साथ समझौता किया था।
- इसके कुछ महीने बाद ही मई, 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं को समझौते से अलग करने की घोषणा कर दी तथा तेहरान पर पुनः प्रतिबंध लगा दिए।
- संधि में शामिल अन्य देशों ने ट्रंप से ऐसा न करने की मांग की थी।
- अमेरिका के परमाणु समझौते से बाहर निकलने के बावजूद यूरोपीय संघ ने इस समझौते के साथ बने रहने की घोषणा की है।
- यूरोप में ईरानी सत्ता के विरोधियों की हत्या की साजिशों और ओमान मिसाइल टेस्ट के बाद जनवरी, 2019 में यूरोपीय संघ ने भी ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन ईरान से संबंध समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

नई ई-वाणिज्य नीति

बिजनेस टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, (31 Jan.)

संदर्भ

- 1 फरवरी, 2019 से भारत की नई ई-वाणिज्य नीति प्रभावी हो जाएगी।
- औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (DIPP) ने सभी ई-वाणिज्य कंपनियों को 60 दिन का समय दिया है जिसके अंदर उनको सरकार के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सुधारित नियमों को ध्यान में रखकर सामंजस्य बैठा लेना है।



मुख्य बिंदु

- ऑनलाइन खुदरा विक्रेता उन वेंडरों के माध्यम से अपने उत्पाद नहीं बेच सकते जिनसे उनका कोई इक्विटी हित जुड़ा हुआ है।
- ये कंपनियाँ ब्रांडों के साथ अलग से कोई ऐसी डील नहीं कर पाएंगी कि वे अपना उत्पाद केवल उनके ही प्लेटफॉर्म पर बेचें।
- ऑनलाइन खुदरा विक्रेता अपने प्लेटफॉर्म से सभी वेंडरों को उत्पाद बेचने का समान अवसर देंगे और किसी भी प्रकार से सामान का विक्रय मूल्य प्रभावित नहीं करेंगे।
- ई-वाणिज्य कंपनियाँ वेंडरों की इन्वेंटरी को नियंत्रित नहीं करेंगी।
- यदि ई-वाणिज्य खुदरा विक्रेता किसी वेंडर से 25% से अधिक खरीद करता है तो यह माना जाएगा कि वह उस वेंडर की इन्वेंटरी को नियंत्रित कर रहा है।
- नए नियम के अनुसार कोई भी ई-वाणिज्य कम्पनी बहुत अधिक डिस्काउंट देकर अथवा कैशबैंक देकर, लम्बी वारंटी देकर अथवा अधिक तेजी से डिलीवरी देकर मूल्यों को प्रभावित नहीं करेंगी जिससे कि सब को समान अवसर मिल सके।



प्रभाव और परिणाम

- नई नीति से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले ई-वाणिज्य कंपनियाँ वे कंपनियाँ होंगी जो वैश्विक-स्तर पर काम करती हैं, जैसे - वालमार्ट की फिलपकार्ट और अमेजन।
- इन कंपनियों को नई नीति के अनुसार अपने व्यवसाय के ढाँचे को बदलना अनिवार्य हो जायेगा। नए नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने 60 दिन का समय दिया है। लेकिन अमेजन और फिलपकार्ट इस समय-सीमा को 4-6 महीने बढ़ाने का अनुरोध कर रही है।
- नये नियमों के कारण इन दो कम्पनियों को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है।
- नई नीति के कारण फिलपकार्ट के शेयर-मूल्यों में 50 बिलियन डॉलर की कमी देखने को मिली है।
- अमेजन के शेयरों के मूल्य भी 5.4% घट गये हैं।



डिजिटल करेंसी 'ASER'

पायनियर, (31 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने संयुक्त डिजिटल करेंसी 'अबेर' (Aber) लॉन्च की है।
- इस संयुक्त डिजिटल मुद्रा का उपयोग दोनों देशों के मध्य ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बीच वित्तीय भुगतान के लिए किया जायेगा।



इससे लाभ

- इस डिजिटल मुद्रा के द्वारा वित्तीय विनिमय के लिए एक और विकल्प उपलब्ध होगा।
- आरंभ में इस मुद्रा का उपयोग सीमित बैंकों में किया जायेगा, बाद में इसे धीरे-धीरे अन्य स्रोतों द्वारा भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस मुद्रा की तकनीकी, आर्थिक तथा कानूनी आवश्यकता का अध्ययन करने के बाद इस मुद्रा के उपयोग का विस्तार किया जायेगा।
- डिजिटल मुद्रा अबेर केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों के बीच डिस्ट्रिब्यूटेड डाटा के उपयोग पर निर्भर है। यह ब्लॉकचेन पर आधारित मुद्रा है।



ब्लॉकचेन तकनीक क्या है?

- ब्लॉकचेन एक प्रकार का डिजिटल बही खाता है, इसमें डाटा क्लाउड में सुरक्षित रखा जाता है। यह डाटा स्टोरेज की सुरक्षित प्रणाली है।
- इसमें डाटा को कॉपी किये बिना विकेंट्रीकृत किया जाता है।

- यह काफी सुरक्षित व पारदर्शी है।
- इस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- इसके अलावा वित्तीय लेन-देन, क्राउड-फंडिंग, गवर्नेंस, फाइल स्टोरेज और इन्टरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है।

डिजिटल मुद्रा के लाभ

- डिजिटल मुद्रा का लेनदेन मुख्यतः इंटरनेट पर होता है। डिजिटल बॉलेट एक तरह का अकाउंट है जिसमें आप अपनी डिजिटल मुद्रा रखते हैं।
- इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल मुद्रा का एक डिजिटल बॉलेट से दूसरे डिजिटल बॉलेट में ट्रांसफर किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए इसे सुरक्षित माना जाता है।
- डिजिटल बॉलेट को फोन, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है।
- डिजिटल मुद्रा को किसी भी अन्य मुद्रा जैसे रुपया, डॉलर आदि के बदले में डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज के तहत खरीदा जा सकता है।
- डिजिटल मुद्रा को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। लाइटकोइन, एथ्यरम, बिटकॉइन आदि सभी डिजिटल मुद्राओं के लोकप्रिय उदाहरण हैं।

स्वस्थ भारत यात्रा का समापन

इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू, (31 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नेतृत्व में चलाई गई अखिल भारतीय 'स्वस्थ भारत यात्रा' अभियान का 29 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय राजधानी के कर्नाट प्लेस में समाप्त हो गया।
- यह यात्रा लोगों को सुरक्षित भोजन खाने और स्वस्थ रहने के बारे में जागरूक करने के लिए निकाली गई थी।



- यह अभियान पिछले साल 16 अक्टूबर को शुरू किया गया था जिसमें तमिलनाडु को अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है।
- स्वस्थ भारत यात्रा 100 दिन का कार्यक्रम था।



क्या है?

- छह अलग-अलग स्थानों लेह, पणजी, तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी, कोलकाता और अगरतला से छह अलग-अलग मार्गों पर आयोजित किया गया।
- इसमें कुल 10,000 से अधिक स्वयंसेवक साइकिल चालकों ने 36' राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में बीस हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की।

- साइकिल यात्रियों ने 'ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट फोर्टिफाईड' (साफ, स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्व मिली खाद्य वस्तुओं) के सेवन का संदेश फैलाया।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने "ईट राईट इंडिया पहल" के लिए स्वस्थ भारत यात्रा की शुरुआत की थी।
- इस यात्रा में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया। इसके तहत 21,000 "ईट राईट चैपियन" भी घोषित किये गये।
- इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन, स्वस्थ रहने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में जागरूक करना था।
- इसके लिए देश भर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लगभग 7,500 साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया।

पुरस्कार विजेता राज्य

- सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य:** तमिलनाडु।
- तीन करोड़ से अधिक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य:** गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र।
- तीन करोड़ से कम जनसँख्या वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य:** पंजाब, गोवा और दिल्ली।
- विशेष पुरस्कार:** जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखण्ड को प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'एफएमसीजी उद्योग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- इस उद्योग में अच्छी अर्थव्यवस्था और घटी हुई मुद्रास्फीति के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि हुई है।
 - यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा सबसे बड़ा उद्योग है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- | | |
|------------------|--------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1, न ही 2 |
2. निम्नलिखित में से आवर्त सारणी के संयोजन की 15वीं वर्षगांठ मनने के लिए किस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है?
- | | |
|----------------|-----------------------|
| (a) यूनेस्को | (b) यूएनडीपी |
| (c) विश्व बैंक | (d) इनमें से कोई नहीं |
3. वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
- | |
|--|
| (a) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया जाता है। |
| (b) यह सूचकांक एक मिश्रित सूचकांक है, जिसमें देशों को रैंक देने के लिए 12 प्रकार के सर्वेक्षण किये जाते हैं। |
- (c) इस वर्ष के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत के तीन स्थानों की कमी आयी है।
- (d) इस वर्ष के सूचकांक में डेनमार्क द्वितीय सबसे कम भ्रष्ट देश है।
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा 'रेल का भविष्य' नामक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है।
 - 'रेल का भविष्य' नामक प्रतिवेदन में वस्तु एवं यात्रियों के लिए रेल सर्वाधिक ऊर्जा बचाने वाला परिवहन का साधन माना गया।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- | | |
|------------------|--------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1, न ही 2 |
5. 'नमक सत्याग्रह स्मारक' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- इसका लोकार्पण महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुजरात के नवसारी जिले के दांडी में किया गया।
 - इस स्मारक में गांधीजी के आदर्शों स्वदेशी आग्रह, स्वच्छता आग्रह और सत्याग्रह का वर्णन एवं चित्रण हुआ है।

- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2
6. 'राष्ट्रपति का अभिभाषण' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- यह अभिभाषण राष्ट्रपति द्वारा नई लोकसभा के पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरम्भ में किया जाता है।
 - राष्ट्रपति द्वारा इस अभिभाषण में मुख्य रूप से आगामी वर्ष के संदर्भ में सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2
7. 'गंगा एक्सप्रेस-वे' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- यह विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा।
 - इसे प्रयागराज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाएगा।
 - इसके रास्ते में 10 रेलवे ओवरब्रिज और 22 फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
- 1 और 2
 - 2 और 3
 - 1 और 3
 - 1, 2 और 3
8. रक्षा अधिग्रहण परिषद् के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- इसका गठन सैन्य सामान शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए वर्ष 2005 में सरकार द्वारा किया गया।
 - इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
 - यह सैन्य सामान के अधिग्रहण के दिशा निर्देश भी जारी करता है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- 1 और 2
 - केवल 2
 - केवल 3
 - उपर्युक्त सभी
9. 'पेमेंट चैनल इंस्टेक्स' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- इसे रूस, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा बनाया गया है।
 - इसका उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों को नजर अंदाज करके इरान के साथ व्यापार करना है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2
10. नई ई-वाणिज्यिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- भारत में यह नीति 1 फरवरी, 2018 से प्रभावी होगी।
 - इस नई नीति में सबसे अधिक प्रभावित वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली कंपनियां होगी।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2
11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और कतर द्वारा संयुक्त रूप में डिजिटल करेंसी 'अबेर' लांच किया गया है।
 - 'अबेर' डिजिटल करेंसी का उपयोग इन देशों के मध्य ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रिल्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बीच वित्तीय भुगतान के लिए किया जाएगा।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2
12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नेतृत्व में स्वस्थ्य भारत यात्रा अभियान शुरू किया गया।
 - स्वस्थ्य भारत यात्रा अभियान में तमिलनाडु को सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2

नोट : 28 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c), 3(d), 4(c), 5(c), 6(b), 7(b)

होगा।

